लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 जनवरी 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -34

"खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते,
अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं।

: मदर टेरेसा

शैक्षणिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है सरकार 3

ख़तरनाक साबित हो रहे ऑनलाइन गेम्स 6

आड़ की पड़छाड़, मेरे नाना की सुसराड़ 8

कोरोना घातक नहीं, मगर सावधानी ज़रूरी

विशेष प्रतिनिधि

कोरोना के फिर से सक्रिय होने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में बचाव एवं सुरक्षा के कार्यों में एकाएक तेजी लाई गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन की प्रसार गति को भी ध्यान रखा जा रहा है। सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के पुख्ता प्रंबंध किए गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार 25 जनवरी तक कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोविड अनुरूप नियमों का पालन करने के लिए सख़्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोविड-19 के विषय में समय-समय पर जिला उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संपर्क बना रहे हैं तथा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर जायज़ा ले रहे हैं। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन अभियान तेज़ किया गया है। 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केअर वर्कर्स और 60 वर्ष आयु से अधिक के कोमोरबिटी लोगों को प्रिकॉशन डोज़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है।

नियमों का पालना करते रहें

प्रदेश के सभी लोगों से आग्रह है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। साबुन से हाथ साफ करते रहें। कहीं भीड़ इकट्ठी न होने दें। अपने अपने काम करते रहें मगर सरकार की हिदायतों को ध्यान में अवश्य रखें, उनकी अवहेलना न करें। कुछ जिलों में दुकानें बंद करने की समय सीमा तय की गई है, इसमें प्रशासन का सहयोग करें।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

डरें नहीं, सजग रहें

कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डरें नहीं, सजग रहे, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की दिक्कत आयी थी, उसी समय हमने 50 बेड से ज्यादा के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का निर्णय लिया था इसी कड़ी में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में आज 84 और प्राइवेट अस्पतालों में 54 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं।

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा

दैनिक टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई

कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब तक राज्य में 3.61 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं, जिनमें 2. 10 करोड़ से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1.50 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी खुराक मिल चुकी है। राज्य में दैनिक टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई गई है और दैनिक आधार पर 40,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ाई जाएगी। कोविड-19 के संबंध में सार्वजनिक कार्यक्रमों, विवाह और अन्य समारोहों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आवश्यक प्रतिबंधों के दिशा-निर्देशों को राज्य सरकार ने भी लागू किया है। सभी को मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की हिदायतें दी जा रही हैं। एक जनवरी से सार्वजनिक स्थानों व सरकारी कार्यालयों में वैक्सीन की दोनों डोज़ लगाकर आने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

आरटीपीसीआर लैब चालू

कोरोना से लडने के लिए हरियाणा सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, जो-जो आवश्यक है वह सभी राज्य में उपलब्ध कराया जा रहा है। जब कोरोना आया था तब हरियाणा में एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं थी, आज एक जिले को छोड़ शेष सारे जिलों में आरटीपीसीआर लैब स्थापित है। जिस जिले में नहीं वहां भी जल्द लगने वाली है। जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी रोहतक एमडीयू में लैब चालू हो चुकी है।

उपायुक्तों के लिए दिशा- निर्देश

» ऑक्सीजन व आवश्यक दवाओं के स्टॉक की समीक्षा की जाए और भविष्य में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस संबंद्ध में आंगनवाड़ी वर्कर तथा शिक्षा विभाग की भी आवश्यकता पड़ने पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

» बस स्टैंड, लघु सचिवालय, मॉल, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पूरी निगरानी रखी जाए और ऐसे स्थानों पर बिना वेक्सीन डोज लगवाए लोगों का प्रवेश निषेध करें।

» विदेश यात्रा करके आने वाले यात्रियों पर पूरी निगरानी रखी जाए, जब तक यह सुनिश्चित न हो, कि उनमें किसी भी तरह के कोविड संबंधी लक्षण नहीं हों। टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक उन्हें होम आईसोलेट करें।

» सभी जिलों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर व आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जाएं।

» व्यक्ति गत स्तर पर कोविड निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर 500 रुपए तथा संस्थाओं पर 5,000 रुपए का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।

डॉक्टरों के लिए कैडर पद

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में एमडी या एमएस डॉक्टरों के लिए स्पेशलिस्ट कैडर पद सृजित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके अलावा, डॉक्टरों को कोई प्रशासनिक कार्य भी नहीं दिया जाएगा और वे अपनी संबंधित विशेषता में ही अभ्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के तहत सरकार विशेषज्ञों के लिए एक विशेष सब कैडर बनाएगी, जिन्हें सलाहकार या वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया जाएगा। इससे पहले एमबीबीएस योग्यता और एमडी/एमएस योग्यता वाले डॉक्टर एक ही कैडर में होते थे। हालांकि, स्पेशलिस्ट कैडर पोस्ट बनने से ये डॉक्टर अपने काम पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और इससे निश्चित रूप से उनके हितों की भी रक्षा होगी। इसके अलावा, विशेषज्ञ कैडर के रूप में डॉक्टरों को अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के बजाय बड़े अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। इससे उनकी पदोन्नति जल्दी सुनिश्चित होगी और उनकी प्रतिभा का सही सदुपयोग संभव होगा।

नई नर्सिंग नीति को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है, यह नीति गत एक जनवरी, 2022 से लागू मानी जाएगी। इस नीति के तहत नर्सिंग कालेज के पास 100 बेड का अपना अस्पताल होना चाहिए या नर्सिंग कालेज की 10 किलोमीटर की परिधि में कालेज एनएबीएच अस्पताल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नर्सिंग कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कालेज में बायोमिट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

विभागीय अधिकारियों की एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जीनोम मशीन को पीजीआईएमएस, रोहतक में कैंसर व इत्यादि बीमारियों की जानकारी हासिल करने के लिए स्थापित करने की योजना है ताकि कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के लिए जीनोम का पता किया जा सके। इसके अलावा पंचकूला स्थित साकेत अस्पताल की फीजियोथेरेपी यूनिट करनाल में शिफ्ट की जाएगी।

रोग नियंत्रण के लिए नग्गल में स्थापित होगी अत्याधुनिक लैब

अम्बाला के नग्गल में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की ब्रांच की स्थापना होगी। उत्तर भारत में यह अपनी तरह की पहली ब्रांच होगी जहां कई गंभीर, नए रोग एवं वायरस की जांच और उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए 2.03 करोड़ रुपए की लागत से जमीन की रजिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी गई है। निर्माण पर कुल 14 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

यह आधुनिक उपकरणों से लैस अत्याधुनिक लैब होगी, जिसमें नई बीमारियों की पहचान, उनके विश्लेषण एवं रोकथाम के तरीकों पर कार्य किया जा सकेगा। नीपा वायरस, जीका वायरस, रैबीज, जूनाटिक रोग, कोविड-19, ओमीक्रॉन, हेपाटाइटिस के अलावा अन्य गंभीर वायरस की जांच और सभी प्रकार के नए टेस्ट इस लैब में हो पाएंगे। पहले जांच के लिए नमूनों को अंबाला से दिल्ली स्थित एनसीडीसी व अन्य शाखाओं में भेजा जाता था।

राज्य व केंद्र सरकार की संयुक्त भूमिका से तैयार होने वाली एनसीडीसी में एकीकृत रोग निगरानी व शोध कार्यों को बढ़ावा, पर्यावरणीय बदलाव पर अध्ययन, प्रयोगशाला में गुणवत्ता एवं क्षमता का निर्माण इत्यादि गतिविधियों पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। यह केंद्र विभिन्न वैक्सीन, दवाइयों व अन्य नैदानिक किट की उपलब्धता के लिए कार्य करेगा। महामारी वैज्ञानिकों, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों व प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए एक अच्छे प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर भी इसे विकसित किया जाएगा।

उपकरण व सुविधाएं

ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, वेटिंग एरिया रूम, लॉबी, कांफ्रेंस हॉल, एडमिन आफिस, सिक्योरिटी रूम, आईटी वीडियो रूम, हेड आफ एनसीडीसी रूम एवं अन्य प्रशासनिक कार्यालय होंगे। प्रथम तल पर सेम्पल कलेक्शन एवं यूटीलिटी रूम, वेटिंग रूम, लॉबी के अलावा, क्लाइमेट चेंज रूम, ईओसी रूम, ट्रेनिंग रूम, आईडीएसपी, ईपीडीमिलॉजी स्टाफ रूम, पैंट्री एवं अन्य रूम होंगे। द्वितीय तल पर लैब व अन्य उपकरण लगाए जाएंगे, जिनमें क्लाईमेट चेंज रूम, माइक्रो लैब बैक्टीरयोलॉजी, एएमआर लैब, लैब टीचिंग एंड डेमो रूम, एएमआर आफिसर रूम, वीरोलॉजी, लौबी एवं अन्य रूम होंगे। तृतीय तल पर नॉन बीएसएल लैब एरिया, बीएसएल-2 लैब एरिया, स्टाफ कॉमन रूम, ओपन टैरेस, पैंट्री एवं अन्य रूम होंगे।

एनसीडीसी ब्रांच का उद्देश्य

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली की संयुक्त निदेशक डा. शिखा वरधान व अंबाला के सीएमओ डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि तीन चरणों में एनसीडीसी ब्रांच का निर्माण पूरा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि एकीकृत रोग निगरानी गतिविधियों को मज़बूत करने में राज्यों का समर्थन करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के संचारी रोगों के लिए रेफरल नैदानिक सेवाओं का विस्तार करना, प्रकोप और आपदाओं के लिए तैयारियों और तत्काल प्रतिक्रिया में राज्यों का समर्थन करना, महत्वपूर्ण उभरती प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्यों में क्षमताओं को बढ़ाना, एकीकृत कीटविज्ञान निगरानी के माध्यम से रोग वाहक, सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण आदि प्रदान करना होगा।

संपादकीय

नव ऊर्जा की शुरुआत

दो महत्वपूर्ण घटनाएं इस कोरोना-लिप्त पखवाड़े में हमें नव-ऊर्जा प्रदान करेंगी। इसी मध्य हमने ऊर्जा-प्राप्ति के सिलसिले का प्रारंभ लोहड़ी, मकर संक्रांति और विवेकानंद-जयंती के साथ किया है।

आगामी 23 जनवरी को समूचा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करेगा और उसके पश्चात विपरीत परिस्थितियों में भी गणतंत्र-समारोह मनाएंगे। मौसम भी बदलेगा और आशा करनी चाहिए कि परिस्थितियों में भी व्यापक स्तर पर बदलाव आएगा।

सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर चुका है। समृद्ध व स्वस्थ ज़िंदग़ी की शुरुआत के दिन हैं। 'खरमास' बीत चुका है और अब हम शुभ घड़ी में शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं।

हमारे पड़ौस में 'लोकतंत्र का पर्व' विधानसभा चुनावों के रूप में मनाया जा रहा है। वहां की ऊष्मा का ताप हमारे प्रदेश तक स्वाभाविक रूप में पहुंचेगा। इन दिनों हमें अपने दायित्वों के प्रति पूर्णतया सचेत भी रहना होगा। यह भी पहली बार हो रहा है कि 'कोरोना' के कुप्रभावों के दृष्टिगत इस बार पड़ौस में चुनाव प्रचार भी 'आनलाइन' ही होगा। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है और हमारे 'लोकतांत्रिक-पर्वों' के स्वरूप में यह एक नया कीर्तिमान भी स्थापित होगा।

हमारे लिए एक सुखद स्थिति यह है कि प्रदेश में सभी कोरोना-प्रतिबंधों के बावजूद विकास की यात्रा में कहीं कोई ठहराव नहीं आया। सारे निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। राज्य के 19 ज़िले 'रैड ज़ोन' में हैं लेकिन कहीं से किस प्रकार की अव्यवस्था की कोई ख़बर नहीं है। 'ऑन लाइन' शिक्षा भी जारी है और ज्ञान के प्रसार एवं प्रचार में कहीं कोई विघ्न नहीं पड़ा।

इन परिस्थितियों में जीवन में स्वाभाविक रूप से आए आत्म-अनुशासन को हम अपनी जीवनशैली का एक अंग भी बना सकते हैं। हम सभी सुखी, निरोग और 'सर्वे भद्राणि पश्यन्तु' के मार्ग पर निरंतर चलते रहें, यही सबकी कामना है।

सुखद बात यह है कि 'आनलाइन' उद्घाटनों, सम्बोधनों और केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण वार्ताओं का सिलसिला अबाध रूप में जारी है। स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण सावधानियों के बावजूद कहीं भी भय, आतंक या ठहराव दिखाई नहीं देता। यही प्रशासन तंत्र व समाज तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है।

- डा चंद्र त्रिखा

सूक्ष्म सिंचाई के लिए सोलर वाटर पम्प

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान' (पीएमकुसुम) के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने में हरियाणा सोलर वाटर पम्पों के संचालन के साथ देश का अग्रणीय राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रतीकात्मक उदघाटन कर किसानों को सोलर पंप प्रदान किए। इन पम्पों पर सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इस मौके पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सोलर वाटर पम्पिंग प्रोग्राम की पुस्तिका तथा किसानों के लिए उपयोगिता पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 50 हॉर्स पावर से कम बिजली के ट्यूबवैल, जो खेती के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं, उन्हें सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश दिए। इस मौके पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थित थे। प्रदेश के जिलों से उपायुक्त तथा नव एवं नवीकरणीय विभाग के अधिकारी ऑनलाईन जुड़े।

मुख्यमंत्री ने सौर पम्प लगाने वाली हिसार की महिला किसान कृष्णा व त्रिलोक सिंह व नूह से शशि आहूजा व ईसाक खान से संवाद किया और उनसे योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बातचीत के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि उन्हें केवल 25 प्रतिशत राशि ही खर्च करनी पड़ी है, शेष राशि सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाएं और सरकार की हर खेत को पानी देने की योजना को लोगों तक पहुंचाए।

सौर ऊर्जा प्रणाली अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 तक केवल 492 सोलर पम्प ही लगवाए गए थे। वर्तमान सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया। इसके पहले चरण में 50 हजार सोलर पम्प सेट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली अनिवार्य रूप से लगाई गई है ताकि वहां की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सके और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में दिया जा सके। पिछले सात वर्षों में 25,897 सोलर पम्प सेट लगाए हैं और इस वर्ष 13,800 पम्प सेट लगाने का कार्य प्रगति पर है।

किसानों को सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य लगभग 80 लाख एकड़ भूमि है। इसमें से 75 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है। शेष भूमि पर सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हर वर्ष किसानों को लगभग 6,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। सौर ऊर्जा को अपनाने से सब्सिडी का भार भी कम होगा और पानी की बचत होगी। इससे किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी।

50 हजार सोलर पम्प लगेंगे

बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की जो नींव मुख्यमंत्री ने रखी थी, उसी के फलस्वरूप हम बेहतर कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई टी के साथ पावर का तीसरा स्थान है जिससे शत प्रतिशत लोग जुड़े है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 22 हजार सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य दिया है जिसे पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 22-23 में 50 हजार सोलर पम्प लगाए जाएंगे।

ई-मोबिलिटी के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'

हरियाणा में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए पांच 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' खोले जाएंगे। इनके अलावा, 20 आईटीआई या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर आरंभ किए जाएंगे। यह जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने 'हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पोलिसी' का ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए बुलाई गई उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एमएसएमई एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी।

डिप्टी सीएम ने ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए राज्य में पांच 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' खोले जाएंगे जिनको प्रत्येक को पांच करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार 20 या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर आरंभ किए जाएंगे जिनको 25-25 लाख की वित्तीय मदद की जाएगी। उन्होंने यह भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शोध एवं अन्य क्षेत्र में धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी, बशर्ते उच्च गुणवत्ता का कार्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी 'ई-व्हीकल' खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-व्हीकल निर्माता कंपनियों, प्रयोग करने वाले वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके 'हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पोलिसी' बनाई जा रही है जिसमें उनको विशेष छूट दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोपहिया, तिपहिया तथा चारपहिया ई-व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 में राज्य में ई-व्हीकलों की भारी तादाद हो। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिए बनाई जा रही प्रदेश की 'हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पोलिसी' पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट हो।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन रहा हरियाणा

हरियाणा ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए 'लॉजिस्टिक्स एज एक्रोस डिफ्रेंट स्टेट्स (एलईएडीएस-2021)' रिपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई है।

हरियाणा को लीड्स-2021 सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभारने में प्रदेश सरकार की सक्रिय नीतियों, बेहतरीन ढंग से विकसित बुनियादी ढांचे व विभिन्न सेवाओं का योगदान रहा है। क्योंकि वर्ष 2019 में हरियाणा जहां इस रिपोर्ट में छठे स्थान पर था, वहीं राज्य सरकार के प्रयासों से इस बार चार स्थानों की सीढ़ी चढ़ते हुए प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रसद में दक्षता 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगी।

हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई 'लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी-2019' प्रदेश में रसद पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। उक्त रिपोर्ट में हरियाणा ने शीर्ष तीन रैंकिंग में जो दूसरा स्थान हासिल किया है, वह निश्चित रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि हरियाणा में हितधारकों ने पंजाब की तुलना में मौजूदा बुनियादी ढांचे और सेवाओं में अधिक विश्वास प्रदर्शित किया है, इसलिए रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में उछाल आया है।

उच्चतम स्कोर हासिल

» राज्य ने वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता, परिवहन के दौरान कार्गो डिलीवरी की समयबद्धता, संचालन और नियामक पर्यावरण और नियामक सेवाओं की दक्षता जैसे कई संकेतकों के लिए उच्चतम स्कोर हासिल किया है।

» रैंकिंग में यह सुधार राज्य सरकार द्वारा की गई सकारात्मक कदमों में परिलक्षित होता है।

» हरियाणा सरकार ने राजमार्गों के साथ गोदाम की सुविधा लाने के लिए जो अच्छी पहल की है, वह लीड्स-2021 रिपोर्ट में रसद क्षेत्र में किए गए सुधार को परिलक्षित करती है।

» इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में पीएफटी के निजी फ्रेट टर्मिनल की अधिकतम संख्या नौ है जो कि हरियाणा में अधिकतम तीन हैं जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक हैं।

» हरियाणा सरकार द्वारा वेयरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर,लॉजिस्टिक्स पार्क और इंटीग्रेटेड/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना के लिए 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की पूंजी और ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

» सरकार द्वारा रसद के क्षेत्र में कुशल लोगों को सक्षम करने के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत रसद और भंडारण इकाइयों को प्रतिपूर्ति करता है।

» राज्य में लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए सिंगल डेस्क क्लीयरेंस मैकेनिज्म, सेल्फ सर्टिफिकेशन और भूमि अधिग्रहण में सहायता के माध्यम से नियामक व्यवस्था को सरल बनाया गया है।

- संवाद ब्यूरो

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि आदिबद्री सरस्वती के उदगम स्थान पर केंद्र सरकार के सहयोग से एक डैम बनाया जाएगा जिस पर 850 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सररस्वती नदी का पानी सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जाएगा।

प्रदेश में नदियों में प्रदूषण के रियल टाइम डाटा का पता लगाने के उद्देश्य से जिला सीमाओं पर ऑनलाइन वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए वर्ष 2015 से 2021 तक की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के निर्देश हुए हैं।

शैक्षणिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

मनोज प्रभाकर

शिक्षण संस्थानों की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षकों की गुणवत्ता और वचनबद्धता होती है। शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक पहल की गई हैं। वह चाहे स्कूल कालेज हों या यूनिवर्सिटी। नेतृत्व की ईमानदारी व शिक्षकों की मेहनत का परिणाम आज स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। कालेजों का माहौल सुधरा है, छात्र व छात्राओं ने अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया है। हर 20 किलोमीटर पर एक कालेज बनाया गया है। छात्राओं को मुफ्त बस पास की सुविधा भी दी जा रही है। इनके अलावा गरीब परिवार के विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की मदद भी दी जा रही है।

बीते समय में विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों की भर्ती में जरुरत से ज्यादा व्यस्त रहा है। शैक्षणिक सुधार और अनुसंधान पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। किसी संस्था के निर्माण में संकाय का अत्यधिक महत्व होता है। महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का मूल इसके संकाय अर्थात शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्धारित संख्या में संकाय उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है ।

राज्य सरकार की नई नीति के मुताबिक विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं गैर शिक्षक भर्ती की चयन प्रि याओं में कुलपति महोद्य शामिल रहेंगे, जो चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे। समितियों को अधिक व्यापक बनाया गया है। यहां तक कि कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में भी कुलपति की अध्यक्षता का सुझाव है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जहां भी आवश्यक होगा, लिखित परीक्षा आयोजित करेंगे। संबंधित क्षेत्र के दो शैक्षणिक विशेषज्ञ हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा नामित किए जाएंगे, एक शैक्षणिक विशेषज्ञ हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा नामित किया जाएगा और एक विशेषज्ञ कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

गरीब विद्यार्थियों के लिए फीस में बढ़ोतरी

शिक्षा अधिनियम-134 ए के तहत निजी स्कूलों में हो रहे दाखिलों को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बताया कि हाल ही में दो लाख रुपए सालाना आय तक के वर्ग में 40 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी थी जिनमें से 12 हजार का प्रवेश हो चुका है। निजी स्कूलों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि पांचवीं कक्षा तक विद्यार्थियों की मासिक फीस 300 रुपए से 500 रुपए तथा आठवीं तक के विद्यार्थियों की फीस 500 से 700 रुपए कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से दी जानी वाली इस फीस का करीब 5 करोड़ रुपए सालाना व्यय होगा।

शिक्षा बजट में 125 प्रतिशत तक वृद्धि

उच्च शिक्षा के बजट में भी पिछले 5 वर्षों में 125 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो हरियाणा में शैक्षिक परिदृश्य को सुधारने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 22 राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। जाट-पाली, महेंद्रगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा, 23 निजी विश्वविद्यालय, एक प्रतिष्ठित संस्थान और 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

मेवात में अध्यापकों की पूरी होगी कमी

मेवात संवर्ग में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 8506 पद स्वीकृत हैं। इस समय नूह जिले के कुल 938 राजकीय विद्यालयों में 4325 अध्यापक कार्यरत हैं। मेवात संवर्ग के उच्च विद्यालयों में 2015 से अब तक कुल 93 प्रधानाचार्य तथा 91 मौलिक शिक्षा मुख्य अध्यापक पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, सीधी भर्ती द्वारा कुल 619 मौलिक अध्यापकों की भर्ती की गई है।

मेवात संवर्ग में पीजीटी के 315, टीजीटी के 370, और पीआरटी के 952 पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। आयोग ने जानकारी दी है कि भर्ती प्रि या लगभग 4 से 5 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि जहां तक पदोन्नति के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के पदों को भरने का संबंध है तो उन पदों को भरने की प्रि या आरंभ कर दी गई है।

प्रदेश में कुल 173 सरकारी महाविद्यालयों में से 6 महाविद्यालय विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा, 97 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिनमें से 35 महाविद्यालय लड़कियों के लिए हैं। राज्य सरकार की 20 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक महाविद्यालय की नीति है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में अहम भूमिका

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी नीति है, जो देश में उच्च शिक्षा का चेहरा और परिदृश्य बदल देगी। हरियाणा इस शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है। यह नीति विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए सशक्त बनाने की परिकल्पना करती है। एनईपी को 2030 तक लागू किया जाना है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे 2025 तक ही लागू करने का फैसला किया है।

प्रदेश के स्कूलों में 53,68,539 विद्यार्थी

प्रदेश में वर्तमान में 24,867 विद्यालय हैं, जिनमें से 14,473 सरकारी और 10,394 निजी विद्यालय हैं। इनमें 138 संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं। आगामी दिनों में मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

इस समय प्रदेश के स्कूलों में कुल 53,68,539 विद्यार्थी हैं। इनमें से सरकारी स्कूलों में 25,30,868 जबकि निजी स्कूलों में 28,37,671 विद्यार्थी हैं। राज्य के स्कूलों में प्रधानाचार्य से लेकर क्लास-4 तक के 1,37,895 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 96,535 पद भरे हुए हैं।

राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से अधिकतर विद्यालय सह-शिक्षा विद्यालय हैं। वर्तमान में राज्य में 14,473 विद्यालयों में से 12,664 विद्यालय सह-शिक्षा वाले हैं और 1809 कन्या विद्यालय हैं।

हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन के कलाक्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए कलकत्ता में आयोजित भारत सांस्कृतिक उत्सव में संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति डा. सोमा बंधोपाध्याय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाज़ा गया।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई हैं। सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारियों को इस दिशा में आगे कदम उठाने के निर्देश दिए हुए हैं।

उम्मीदों का

मनोज प्रभाकर

नव वर्ष 2022 का आगाज़ हो चुका है। पिछले दो वर्ष कोरोना महामारी व कुछ अन्य मसलों में जैसे बीते उस तरह बीतना नहीं चाहिए था। महामारी के चलते काफी नुकसान हुआ जिसे भूलने के अलावा कोई अन्य रास्ता भी नहीं है। जो बिसर गई, सो बिसर गई। नई सुबह हो चुकी है, नई उमंग व नए उत्साह के साथ जीवन को आगे बढ़ना है। यह नैसर्गिक भी है। खुद, परिवार, समाज व राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। जरुरत है नए हौंसलों की, सकारात्मक सोच की, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की। राज्य की मनोहर सरकार ने सबको साथ लेकर सबके समान विकास का संकल्प दोहराया है ताकि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और हर परिवार सुख सुविधाओं से समृद्ध हो। राज्य सरकार ने इसके लिए अनेक नई कल्याणकारी योजनाओं का एलान किया है तथा पुरानी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ष-2022 सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

मनोहर सरकार ने सेहत से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के तमाम परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पांच ट्रिलियन इकॉनोमी करने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में टारगेट तय कर लिए हैं। 'आत्म निर्भर हरियाणा' और 'आत्म निर्भर भारत' के सपने को साकार करते हुए हम प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है और पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार हुआ है। इनमें विशेषकर सड़कों का सुधार उल्लेखनीय है क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी सड़कें अच्छी होंगी तो हमारे प्रदेश की इकॉनोमी भी अच्छी रहेगी।

रोजगार नीति को गति देगी 'पदमा'

वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को गति देने के लिए हरियाणा सरकार 'पदमा' योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के मालिकों को अधिक से अधिक फायदा होने तथा गांव में रोजगार के अवसर बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब पचास एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। राज्य सरकार ने ब्लॉक-वाइज कुछ उत्पाद तय किए गए हैं जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी।

राज्य के कई गांवों में हुनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक प्रॉडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको मजबूरी में लोकल लेवल पर कम दामों पर बेचना पड़ता है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मुताबिक राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रॉडक्ट के लिए एक कलस्टर बनाया जाए, जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सकें। इस कलस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सैंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।

निजी संस्थाओं में नौकरी

प्रदेश सरकार ने निजी संस्थानों में रोजगार में हरियाणा वासियों को 75 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का नियम बनाया है परंतु यदि उद्योगों को उपयुक्त व्यक्ति ना मिले तो वे उपायुक्त से अनुमति लेकर बाहर से भी व्यक्ति को रोजगार पर रख सकते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक उद्यमियों से सलाह करके उनकी सहमति से इस नियम में 50 हजार रुपए मासिक से कम करके 30 हजार रुपए मासिक किया गया है अर्थात् 30 हजार रुपए मासिक तक की नौकरियों पर यह नियम 15 जनवरी से लागू होगा।

स्टार्टअप को प्रोत्साहन

एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 1500 स्टार्टअप को रोजगार दिया गया है तथा 4 हजार आवेदन अभी प्रोसेस में हैं। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि पड़ौसी राज्यों से अधिक है। हरियाणा में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी सरकारी, गैर सरकारी, उद्योगों आदि में मिलाकर हर वर्ष पांच लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश से निर्यात को भी बढाकर 2 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में हरियाणा से लगभग 85 हजार करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है।

अंत्योदय मेलों के जरिए रोजगार

गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में कई योजनाएं लेकर आएगी। सरकार का लक्ष्य लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पहले चरण में 156 मेले आयोजित किए गए थे। इसमें डेढ़ लाख परिवारों में से 90 हजार ने हिस्सा लिया। इसमें आए बहुत से लोगों का ऋण भी मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बताया कि 31 मार्च तक एक लाख परिवारों को यह सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

गांवों में उद्योग लगाने की योजना

राज्य सरकार ने पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी 'पंचायत लैंड लीज पॉलिसी' बनाएं जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी-खासी आमदनी हो। इस आमदनी से गांव में अधिक से अधिक विकास हो सकेगा। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गांवों में गैर-कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को अपने नजदीक ही रोजगार मिल सके। इससे जहां उद्योगपतियों को आसानी से कामगार मिलेंगे वहीं शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी।

नाबार्ड का सतत सहयोग

कोविड-19 वैश्विक महामारी के बावजूद भी हरियाणा राज्य में विकास की गति में कमी नहीं आई और हरियाणा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 44 प्रतिशत अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में देश में अग्रणी राज्यों में रहा। राज्य ने वर्ष 2019-20 में 715 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 1030 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की, जो प्रदेश में हो रही उन्नति को दर्शाता है।

वर्ष 2021 -22 के दौरान नाबार्ड द्वारा परियोजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1242 करोड़ रुपये अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, 1400 करोड़ रुपए के संवितरण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 536 करोड़ रुपये से अधिक की अदायगी नाबार्ड द्वारा की जा चुकी है।

वित्त एवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद ने सूक्ष्म सिंचाई, भंडारण, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी प्रसंस्करण और मत्स्य के बुनियादी ढांचा फण्ड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूरल इन्फ्रास्ट्र• र डिवलेपमैंट फंड (आरआईडीएफ) के तहत ब्याज की दर 2.75 प्रतिशत है।

सोनीपत के बड़ी में बन रहा मेगा फूड पार्क का कार्य 31 मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। इस पर लगभग 169 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी प्रकार गन्नौर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार 545 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है, जिसके लिए नाबार्ड 1600 करोड़ की सहायता प्रदान कर रहा है।

कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में इंटरप्रेन्योर्स व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने लिए यस बैंक के साथ समझौता किया है। इससे किसानों, छात्रों और उद्यमियों के स्टार्टअप के लिए सहायता मिलेगी।

हरियाणा सरकार द्वारा 'दीनबंधु छोटुराम यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलोजी, मुरथल से विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में वीकेंड/पार्टटाईम(बी.टेक/एम.टेक) की डिग्री को नियमित स्नातक/परास्नातक डिग्री के समान मानने का निर्णय लिया है।

बस 2022

आवास योजना

हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड ने किफायती आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने हिसार, करनाल, कुरूक्षेत्र, अंबाला आदि शहरों को टाऊन प्लानिंग स्कीम के तहत विकसित करने का कार्य शुरू किया है। इतना ही नहीं, निजी संस्थाओं के सहयोग से राज्य के गुडग़ांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बल्लभगढ़ आदि शहरों में रिहायशी प्लॉट ग्रुप हाऊसिंग, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और आईटी टाऊनशिप विकसित करने का कार्य भी शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को करीब 20 हजार किफायती आवास उपलब्ध करानी की योजना है। इनमें से 13 हजार मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।

सड़क मार्ग व ओवरब्रिज

करनाल-मेरठ रोड़ को कुछ स्थानों पर फोर-लेन करने, कुछ स्थानों पर सिक्स-लेन करने तथा कुछ ओवरब्रिज के निर्माण कार्य 2022 में जल्द पूर्ण होने की उम्मीद है।

भिवानी से खरक गांव तक मार्ग को फोर-लेन तथा रोहतक मार्ग को चरखी दादरी रोड़ से मिलाने के लिए भिवानी-बाईपास के निर्माण के प्रस्ताव हुए हैं। फोर-लेन का पिंजौर बाईपास निर्माण तथा समालखा से अट्टा तक के रोड़ को चौड़ा करने, गांव खोजकीपुर के नजदीक यमुना नदी पर एच-एल ब्रिज बनाने,रेवाड़ी जिला के गांव पाली में फोर-लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाने के कार्य की भी समीक्षा हो चुकी है। हिसार में रेवाड़ी-भटिंडा रेलवे लाइन पर जिंदल चौक से सूर्य नगर तक रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश हुए हैं।

रोहतक शहर में कच्चा बेरी रोड़ पर टू-लेन एलिवेटिड रेलवे ओवरब्रिज बनाने, गुरूग्राम में दिल्ली-रेवाड़ी लाइन पर फोर-लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाने, करनाल में दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन पर फोर-लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाने, रेवाड़ी जिला में रेवाड़ी-नारनौल रोड़ से रेवाड़ी- झज्जर रोड़ का लिंक रोड़ का निर्माण , सोनीपत-राठधना-नरेला रोड़ का अपग्रेड करने, गुरूग्राम में पुरानी दिल्ली-जयपुर रोड़ पर फ्लाइओवर तथा अंडरपास का निर्माण करने, गांव जठलाना के पास यमुना नदी पर एचएल ब्रिज बनाने, रोहतक में शीला बाइपास चौक पर फ्लाइओवर बनाने, कुरूक्षेत्र में गीता द्वार से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट तक रोड़ को सिक्स-लेन करने के अलावा नांगल चौधरी के लॉजिस्टिक हब से सिक्स-लेन रोड़ बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए इन्हें निर्धारित समय में पूरा करने की उम्मीद जताई गई है।

प्रगतिशील किसान सम्मानित होंगे

हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों की पहचान कर उन्हें राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है ताकि प्रगतिशील किसान अन्य किसानों को सर्वोत्तम एवं नवीनतम कृषि प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।

कृषि फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणालियों व टिकाऊ कृषि जैसी नवीनतम तकनीकी को अपनाने वाले किसानों को इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए पांच लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए दो किसानों को तीन-तीन लाख रुपए तथा तृतीय पुरस्कार के लिए पांच किसानों को एक-एक लाख रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर सांत्वना पुरस्कार के रूप में 88 किसानों को 50-50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

मॉडल संस्कृति स्कूल बढ़ाए जाएंगे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाएगी। बीते दिनों हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

पंचायती चुनाव

प्रदेश में पंचायती चुनाव लंबित हैं। यह विषय कोर्ट में विचाराधीन है। न्यायालय का निर्णय आने के उपरांत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं को लेकर कानून में बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार चाहती है कि इन बदलाव के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं। हाईकोर्ट का फैसला जनवरी माह में आने की संभावना है। पंचायती चुनाव कानून संशोधन के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत और बीसी-ए वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण देने का मसला लंबित है।

आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन

आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए रोहतक और पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आर्म्स लाइसेंस को सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया जाएगा, न की प्रतिष्ठा के लिए।

परिवार पहचान पत्र से मिलेगा राशन

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। अब जनवरी-2022 से राशन डिपुओं पर राशनकार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलना संभव होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या जुड़ने या घटने का हिसाब भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से होगा। परिवार पहचान पत्र के साथ जन्म-मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और अब भविष्य में विवाह पंजीकरण को भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा।

» महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास गांव में गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

» प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में अंबाला में बनाए जा रहे युद्ध-स्मारक में म्यूजियम, ओपन एयर थियेटर, ऑडिटोरियम, मैमोरियल टॉवर के पूरा करने में आ रही दिक्कतों को दूर कर मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश हुए हैं।

» अंबाला शहर के सिविल अस्पताल को 200 बैड से बढ़ाकर 300 बैड क्षमता का करने तथा लघु सचिवालय में फेज-3 के प्रशासकीय खंड के निर्माण की परियोजना है।

» गुरूग्राम में बनाए जा रहे 'टॉवर ऑफ जस्टिस'(न्यू ज्यूडिशियल कंपलेक्स) के 'की-प्लॉन' से लेकर अभी तक किए गए कार्यों का अध्ययन हुआ है। इसको जून 2022 तक फाइनल करने का लक्ष्य रखा गया है।

» रेवाड़ी में जेल के नए भवन के निर्माण में को 31 अक्तूबर 2021 तक कार्य पूरा करने के निर्देश हैं।

» सोनीपत में निर्माणाधीन 'डॉ. बी.आर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' के कार्य को निर्धारित अवधि तक पूरा करने का वादा हुआ है।

» यमुनानगर के मुकंद लाल सिविल अस्पताल को 200 बैड की क्षमता का करने, पंचकूला में 'हरियाणा स्टेट आर्कियोलोजिक्ल म्यूजियम' का निर्माण, करनाल के घरौंडा में एनसीसी अकादमी भवन, पीजीआई रोहतक में शिक्षकों के लिए मकानों के निर्माण कार्य की समीक्षा हुई है।

» गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज जींद को जुलाई 2023 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश हुए हैं।

छात्राओं के लिए निः शुल्क बस सेवा

हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए निः शुल्क बस सेवा शुरू करने की योजना के तहत डाटा एकत्रित कर लिया गया है, अब प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारियों को इस दिशा में आगे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां गांव से शहर के सरकारी कालेजों में दैनिक रूप से पढ़ने जाती हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा फ्री बस पास की सुविधा आरंभ की हुई है। महानिदेशक की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों-कम-जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि छात्राओं को जल्द से जल्द यह सुविधा मुहैया कराई जाए।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने भू-जल के सभी उपयोगकर्ता (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) जो भू-जल निकालते हैं या निकालना चाहते हैं, उन्हें एनओसी के लिए आवेदन 31 जनवरी तक आवेदन करने का निर्देश दिया है।

बीपीएल व ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु यदि किसी कारणवश कोई निजी विद्यालय अभी तक ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाया है तो उनके लिए विभाग द्वारा 6 जनवरी से पोर्टल पुनः खोल दिया गया है।

मिशन ओलंपिक में जुटे पहलवान

टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नई खेल नीति के तहत 1100 खेल नर्सरियों स्थापित की जा रही हैं। जो स्कूल इन नर्सरियों को लेने के इच्छुक है वे 20 जनवरी तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है। अभी तक पूरे प्रदेश में मात्र 111 नर्सरियां ही संचालित हो रही थी। नर्सरियों की बढ़ाई संख्या में 500 खेल नर्सरियों को खेल विभाग व 600 खेल नर्सरियों को प्राइवेट संस्थानों को दिये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है।

हर खेल नर्सरी में 20 से 25 खिलाड़ी होंगे। पांच खिलाड़ियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। खेल विभाग ने इन खेल नर्सरियों का कार्यकाल एक अप्रैल से आगामी 31 जनवरी तक रहेगा। जो खिलाड़ी नर्सरियों के लिए चयनित किये जायेंगे उन खिलाड़ियों को दो श्रेणी में रखने का प्रावधान है। प्रथम श्रेणी में 8 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी को रखा गया है जबकि दूसरी श्रेणी में 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को स्थान दिये जाने का प्रावधान है। दो श्रेणियों में रखे जाने वाले इन खिलाड़ियों में 8 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 1500 रुपए की

छात्रवृति खुराक के रूप में प्रति माह प्रदान की जायेगी व 15 से 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को यह राशि 2,000 रुपए प्रदान की जायेगी।

हाकी कोच देवेद्र गुलिया के अनुसार सरकार द्वारा नर्सरियों को बढ़ावा देने से खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा होगा। अच्छा टेलेंट उभर कर आयेगा। कुश्ती कोच मनोज मलिक के अनुसार खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए मैदान में आना पड़ेगा। खिलाड़ियों को मिलने वाली खुराक कमजोर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सहायक होगी।

खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन के अनुसार प्रदेश में 1100 नर्सरियां खोली जा रही हैं। पूरे प्रदेश में चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में खिलाड़ियों की नींव मजबूत होगी।

महिला पहलवान

देहात में लड़कियां का रूझान कुश्ती के प्रति बढ़ा है। कुश्ती में कामयाबी को लेकर प्रदेश के अनेक गांवों में लड़कियां अभ्यास कर रही हैं। रोहतक की कुश्ती अकादमी में 26 लड़कियां कुश्ती का अभ्यास कर रहीं हैं। अकादमी की कई लड़कियों का वर्ष 2021 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड फ्री स्टाईल महिला कुश्ती चैंपियनशिप में चयन हुआ था।

यहां की करीब दस लड़कियां अलग-अलग आयु वर्ग में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रही हैं। प्रियंका 57 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाईल कुश्ती वर्ग की खिलाड़ी है। भतेरी 65 किलो वर्ग भार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन लगातार कर रही है। उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वह पैरिस ओलंपिक तक पहुंचने व मेडल जीतने का सपना लेकर अभ्यास कर रही है। युवा पहलवान पिंकी का लक्ष्य देश के लिए खेलना है। वह सवेरे- सांय 4-4 घंटे कुश्ती का अभ्यास करती हैं। अभ्यास क बाद पौष्टिक आहार, बादाम, दूध,मखन, दही व हरी सब्जियों का सेवन करती हैं।

नीतिका 57 किलो भार वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करती आई है। उनका सपना ओलंपिक में मेडल जीतने का है। वो पिछले तीन वर्ष से कुश्ती का अभ्यास कर रही हैं। मंजू, पिंकी, ईशा पूनिया, तनू व मंजू का सपना है कि वे भी ओलंपिक में मेडल जीतें।

कोच बिजेंद्र ने बताया की वर्ष 2016 में कुश्ती अकादमी की शुरूआत हुई थी। यहां मिटटी व मैट दोनों प्रकार के अभ्यास के लिए सुविधा है। सप्ताह भर का शैड्यूल बना कर प्रशिक्षण दिया जाता है। खेल की बदौलत यहां के कई खिलाड़ियों को रेलवे, पुलिस व अन्य महकमों में सरकारी नौकरी मिली है।

-सुरेंद्र सिंह मलिक

ख़तरनाक साबित हो रहे ऑनलाइन गेम्स

डब्ल्यूएचओ ने ऑनलाइन गेम्स को बीमारी माना

कोरोना व लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन गेम्स का चलन बढ़ा है। इससे बच्चों की मानसिक व शारीरिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन-गेमिंग की बढ़ती प्रवृति से विद्यार्थियों के अभिभावकों को सचेत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) ने भी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज (आईसीडी) के ताज़ा संस्करण में इसे शामिल किया है। पहली बार इसे बीमारी यानि गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिसर्च के अनुसार कंपनियां आरंभ में मुफ़्त में सर्विस देकर युवाओं को आकर्षित करती है और फिर उनसे लाखों कमाती है। इन गेम्स के माध्यम से कंपनियों का करोड़ों रुपए का मुनाफ़ा होता है।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के संभावित खतरों को लेकर परिजनों और शिक्षकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव

बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए पूरा समय स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। इस आदत के कारण बच्चों में कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे पोस्चर ख़राब होना, हार्ट अटैक, मोटापा, अवसाद और लत आदि के शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आदत होने के कारण गेमर्स अपना अधिकतर समय ख़राब कर देते हैं। अपनी नींद पर भी ध्यान नहीं देते है। आमतौर पर बच्चे हिंसक गेम्स खेलते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। बच्चे में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन के भी लक्षण

दिखने लगते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और पढ़ाई में ख़राब प्रदर्शन आता है। ऑनलाइन गेम्स के कारण कई बार रुपए की लेन-देन के कारण भारी नुक़सान सहना पड़ता है। नासमझ बच्चे मोबाइल से अपने माता-पिता के बैंक डिटेल को लिंक करके खेल में सारा अकाउंट खाली कर देते हैं। इसका ख़ामियाज़ा माता-पिता को सहना पड़ता है।

इन्हें हो चुका है नुकसान

यमुनानगर की नौवीं कक्षा की पार्थवी का कहना है कि मैंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेम्स में अपना बहुत समय बर्बाद किया, जिसके चलते मुझे एक बड़े नंबर का चश्मा लग चुका है आज मुझे पछतावा होता है। वह अपनी उम्र के सभी बच्चों को यह सलाह देना चाहती है कि मोबाइल व लैपटॉप का प्रयोग केवल और केवल अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए ही करें तो उनके लिए बेहतर होगा। झज्जर का दूसरी कक्षा का रिशभ व चौथी कक्षा की हर्षिका भी ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ ऑनलाइन गेम्स में अपना समय बर्बाद करती है। इसके चलते उनकी माता मनीषा भी हमेशा परेशान रहती हैं। वे कहती हैं कि हिंसक ऑनलाइन गेम्स से बच्चों के व्यवहार में भी ख़ासा परिवर्तन आया है और बार-बार गुस्सा व जिद्द करने लग गए हैं।

> कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक रुन नीलसन कहते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति बरसों तक निकोटिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने पर इनका व्यसनी हो जाता है, इसी आधार पर ऑनलाइन गेम्स को भी व्यसन माना गया। आईसीडी की लिस्ट में गैंबलिंग के अलावा सिर्फ़ गेमिंग को ही लत बताया गया है।

यमुनानगर, शादीपुर के मौलिक विद्यालय के मुख्याध्यापक दर्शन लाल बवेजा का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए बच्चों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किशनपुरा दामला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक श्रीश बेंजवाल का कहना है कि ऑनलाइन गेम्स की लत उन्हें असामाजिक तथा काल्पनिक दुनिया में जीने वाला बना देता है। बच्चों को मोबाइल आदि इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखें। उन्हें योग, व्यायाम, खेलकूद आदि शारीरिक गतिविधियों एवं योग, संगीत आदि की तरफ़ लगाएं।

मानसिक दुष्प्रभाव

सीनियर रेजीडेंट मनोचिकित्सक आयुष शर्मा के अनुसार ऑनलाइन गेम्स जहां बच्चे से शारीरिक व पढ़ाई में नुकसान पहुंचाता है, वहीं ऑनलाइन गेम्स से बच्चे के मानसिक व व्यवहार में ख़ासा बदलाव आता है। इसके साथ ऑनलाइन खेलना मस्तिष्क के कार्य और संरचना पर प्रभाव डालता है, जिससे दिमागी कार्यों के करने की क्षमता बढ़ सकती है।

-संगीता शर्मा

कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। मोबाईल नंबर 90131-51515 को अपने मोबाइल में सेव करके वाटसएप पर जाकर सर्टिफिकेट टाईप करके भेजना होगा।

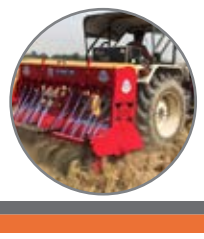

कृषि यन्त्रों, सूक्ष्म सिंचाई यन्त्रों, फसल अवशेष प्रबन्धन के तहत दी जाने वाली सब्सीडी के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरूरी है। किसान अटल सेवा केन्द्रों पर जाकर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करवा लें।

आंगनवाड़ी वर्कर्स को नववर्ष का तोहफ़ा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर को नववर्ष का तोहफ़ा देते हुए उनके हित में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर, 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट पर एक लाख रुपए तथा हेल्पर को 50 हजार रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही, मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने और दो साल (वर्ष 2019-20 और 2020-21) का एरियर देने तथा कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1,000-1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की भी घोषणा की।

वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा। बल्कि राज्य सरकार प्रदेश में आंगनवाड़ी के साथ- साथ क्रैच खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन क्रैच में बच्चों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। इन क्रैच में भर्ती के लिए नए उम्मीदवारों के साथ-साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा।

आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 12 रुपए प्रति माह प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने झज्जर जिले की दो आंगनवाड़ी वर्कर्स की मृत्यु की सूचना सुनकर मौके पर ही उन्हें तुरंत दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा दी। उन्होंने कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया पीडब्ल्यूडी से समीक्षा के बाद पंचायत या यूएलबी द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को लिखित परीक्षा के माध्यम से सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु पॉलिसी लाई जाएगी।

> राज्य में आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने अच्छे ढ़ग से जिम्मेदारी निभाई है। मुख्यमंत्री द्वारा नए वर्ष में प्रदेश में हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स के लिए कई गई नई घोषणाओं से उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और वे आगे भी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी।
>
> **कमलेश ढांडा,**
> **राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास**

दिया जाएगा मोबाइल फोन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोद्योगिकी के आधुनिक युग में नए-नए परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि भविष्य में आंगनवाड़ी भी आधुनिक हों और बच्चों के लिए और बेहतर सुविधाएं शुरू की जाएं। इसी उद्देश्य से सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को विभाग की ओर से एक-एक मोबाइल फोन दिया जाएगा ताकि वे पोषण ट्रैकर ऐप पर अपनी आंगनवाड़ी से संबंधित संपूर्ण डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट रखें।

-संवाद ब्यूरो

खेल-खेल में बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास

हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के आधारभूत ढांचे में सुधार और केंद्रों के कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में आई.सी.डी.एस. के तहत 148 परियोजनाएं (127 ग्रामीण + 21 शहरी) स्वीकृत हैं और 25,962 स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं, के माध्यम से राज्य में चलाई जा रही है। ये केंद्र पूरक पोषहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देख-रेख, संदर्भित सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा प्रदान करते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में 9,006 आंगनवाड़ी केंद्र अपने भवनों में चल रहे है। वर्ष 2020-21 में 16,616 आंगनवाड़ी केंद्रों में आकर्षक एवं रंगदार मेज व कुर्सियां (4 मेज व 16 कुर्सियां प्रति केंद्र) 19.65 करोड़ रुपए की लागत से सप्लाई की गई। वर्ष 2020-21 में 21,375 आंगनवाड़ी केंद्रों मे झूले तथा 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों में सुपर स्लाईड सीनियर 16.94 करोड़ रुपए की लागत से सप्लाई किये गये हैं। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाये गये।

प्ले स्कूल खोलने का निर्णय

मुख्यमंत्री, हरियाणा ने वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 4,000 प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। यह घोषणा दो चरणों में लागू होगी। प्रथम चरण में 2020-21 में 1,135 आंगनवाड़ी केंद्र तथा दूसरे चरण में 2021-22 में 2,865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जायेगा। नई शिक्षा नीति-2020 के विज़न के अनुरूप, सरकार अगले एक साल में आंगनवाड़ियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाएंगी और शेष बचे 21,962 आंगनवाड़ियों के माध्यम से गुणवत्ता परक खेल-खेल में सीख या स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करेगी।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 600 कैलोरीज तथा 18-20 ग्रा. प्रोटीन, बच्चों को 500 कैलोरीज तथा 12-15 ग्रा. प्रोटीन तथा अत्याधिक कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरीज तथा 20-25 ग्रा. प्रोटीन 8 रुपए प्रति बच्चा, 9. 50 रुपए प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 12 रुपए प्रति अति कुपोषित बच्चे को दर से पूरक पौषाहार एक वर्ष में 300 दिन उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में 11.15 लाख बच्चों तथा 3.12 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। योजना के तहत पंजीरी, आलू-पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, गुलगुले, चना मुरमरा तथा मूंगफली मिक्चर दिये जा रहे हैं। पूरक पोषाहार पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में किया जाता है।

आंगनवाड़ी केंद्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ना

आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभपात्रों को स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य के 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में तीन एल.ई.डी. लाईट तथा दो पंखों की व्यवस्था की जायेगी। इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में 9,500 उन आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किया जायेगा जो सरकारी भवनों में चलाये जा रहे हैं। जिनमें से 5,108 आंगनवाड़ी केंद्रों को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ दिया गया है। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा हरेडा को 2,042.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

आंगनवाड़ी भवन निर्माण

वर्तमान में एक आंगनवाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण के लिए 9.95 लाख रुपए की राशि नियत की गई है। यह निर्माण कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के माध्यम से करवाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के बजट में 8,000 लाख रुपए की राशि का प्रावधान वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 180 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु व 2017-18 में अधूरे 935 आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरा करने के लिए किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में 2,004.14 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

पोषण अभियान

पोषण अभियान का लक्ष्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। इस अभियान को राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। पहले चरण में जिला नूह तथा पानीपत को कवर किया गया तथा दूसरे चरण में दस जिलों तथा तीसरे चरण में शेष बाकी बचे जिलों को भी कवर कर लिया गया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रुपए की राशि तीन किस्तों में दी जाती है।

-संगीता शर्मा

अब प्रदेश की मंडियों में फल व सब्जी विक्रताओं को मार्केट फीस नहीं देनी पड़ेगी, राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिशत मार्केट फीस व एक प्रतिशत एचआरडीएफ फीस को माफ़ कर दिया गया है।

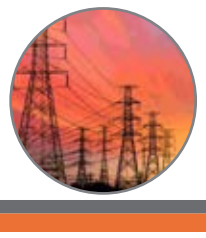

प्रदेश में आम उपभोक्ताओं से लेकर उद्योग व हर क्षेत्र के लिए बिजली आपूर्ति प्रचुर मात्रा में की जा रही है। हाल ही में सरकार द्वारा बिजली दरों में कमी भी की गई जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को काफ़ी लाभ पहुंचा है।

आड़ की पड़छाड़, मेरे नाना की सुसराड़

हरियाणवी बोली की अनमोल थाती लोकोक्ति

जैसे कथन में विशिष्टता लाने के उद्देश्य से भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही कथ्य में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए कथोक्तियों का प्रयोग होता है। कथोक्तियों में, पात्रों के उल्लेख के बिना ही, मात्र संवादों द्वारा किसी भाव, विचार या तथ्य-विशेष का उद्घाटन होता है। कथा की ओर मनुष्य की रुचि जन्मजात एवं नैसर्गिक है। कदाचित् इसी कारण कथोक्तियां, लोकोक्तियों आदि से, अधिक चमत्कारिक और प्रभावशाली होती हैं।

हरियाणा में, लोक-व्यवहार में, मुहावरों और लोकोक्तियों की भांति, कथोक्तियों का भी, प्रचुर प्रयोग होता है। कथोक्तियां हरियाणवी लोक-मानस और गंवई भूमि की उपज हैं। इसी से इनमें सहजता, प्रभाविष्णुता और प्रवाहमयता विद्यमान है तथा ये सीधी हृदय में पैठती हैं। कथोक्तियों के प्रयोग से उसमें एक अनिर्वचनीय रोचकता, मिठास और मार्मिकता आ जाती है। जैसे

आंधा बांटै सीरणी अप-अपणा नै दे - औरां की के फूट-गी, आगा बढ़-कै ले। आई तीज, बिखेर गई बीज - आई होली, भर ले गई झोली। आंधा गुरू आंधा चेला - कूऐं में दोनूं ढ़ेल्लम-ढ़ेल्लां। आपना मारे छां में गैरै। इबै किमै ना बिगड़्या, इबै तै बेटी बाप कै सै। इतनी चीकणी हांडी होती तै कुत्ते ए ना चाट लेते। आड़ की पड़छाड़, मेरे नाना की सुसराड़। आदि।

हरियाणवी-लोकोक्तियों के संदर्भ में डॉ. सुमन मंजरी का कथन है--''हरियाणवी के लोक-अंचल में रहने वाले लोग, बात-बात में लोकोक्तियों का प्रयोग करके, अपने कथन को प्रभावशाली बनाते हैं। पंडितों के शास्त्रार्थ से लेकर पंच-परमेश्वर की चैपाल तक, मुखिया की बैठक से लेकर खेतों और खलिहानों तक, लोकोक्ति का अपना साम्राज्य है।'' यह कथन कथोक्तियों के सन्दर्भ में भी सटीक बैठता है। हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्गों, राह चलते राहगीरों और हल चलाते हलवाहों की बातों में ही नहीं, लड़ते-झगड़ते स्त्री-पुरुषों की भाषा में भी कथोक्तियों का अनायास प्रयोग सहज-सुन्दर होता है, जो कथ्यगत अर्थवत्ता एवं प्रभावशीलता को द्विगुणित कर देता है। कथोक्तियां समूचे मानव-व्यवहार तथा जीवन-रंगों को अपने में समेट लेती हैं। इनमें पीढ़ियों का अनुभव, चिरसंचित ज्ञान, लोक-नीति, चमत्कारिक उपदेश, व्यंग्य-परिहास आदि सभी कुछ समाहित है। जहां ये वाग्विदग्धता का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, वहीं इनका पैनापन 'देखन में छोटा लगे, घाव करे गम्भीर' की उक्ति को चरितार्थ करता है। इनकी विविधता भी द्रष्टव्य है। इन्हें सामान्यतः उपदेशात्मक, नीतिपरक, व्यंग्यात्मक, विरोधाभास-मूलक आदि श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अस्तु, कतिपय हरियाणवी- कथोक्तियां उदाहरणस्वरूप यहां प्रस्तुत हैं।

अभिप्राय यह कि हरियाणवी-कथोक्तियां बड़ी रुचिकर और तथ्यपरक हैं। जैसे गोटा-किनारी चुन्दड़ी के सौंदर्य में और घी-दूध खिचड़ी के स्वाद में वृद्धि कर देते हैं, वैसे ही कथोक्तियां भाषायी सुन्दरता को निखार देती हैं। अपनी संवादमूलक कथात्मकता एवं अतुल अर्थवत्ता के कारण ये सहज ग्राह्य हैं। दो-दो, चार-चार पंक्तियों की ये छोटी-छोटी कथोक्तियां हरियाणवी बोली की अनमोल थाती तो हैं ही, इन्हें अनुभव का आईना कहना भी अनुचित न होगा।

-डॉ. रामनिवास 'मानव'

सुण छबीले बोल रसीले

शहरां तैं कम कोन्या म्हारे गांव

एक बै एक बूढ़ा नहाकै, नए कपड़े पहरकै और हाथ में डोगा लेकै घर तैं चालण की तैयारी में था। उसनै देखकै उसकी पोती बोली- दादा कितोड़ जा सै?

दादा बोल्या- बेटा, बाहर जा सूं, तेरी खातर कितै घर बार देखण।

छोरी बोली- आच्छा दादा, ठीक सै। कोय इसी जगहां देखकै आइये जड़ै गाम की खुली-खुली गाल हों

घर थोड़ा-सा बडा और हवादार हो, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो, आंगन में पेड़ पौधे हों, गलियां में कितोड़ किचड़ ना हो, साफ सफाई वाली हों, मतलब घरां के निकासी के पानी का ठीक बंदोबस्त हो। घर की जिड़ में कोई छोटा -मोटा पार्क हो तो बढ़िया रहगा।

दादा बोल्या- बेटी जै इसा बढ़िया घर पाज्यागा, तो उड़ै मैं ए ना रहल्यूंगा।

छोरी आपणे दादा के मुहं कान्या देखती रहगी।

- रसीले ये सारी सुख सुविधा कित पावैं सैं। घर पा ज्या सै तो बर नहीं, और बर पाज्या सै तो घर नहीं। इनकी भी देखी जा। अड़ौसी पड़ौसी तो कोनी देखे जाते। वे ठीक होंगे तो ठीक और गलत होंगे तो भी ठीक। वे तो बदले ना जां। गाम में और शहर में फर्क सै। शहर में तो किसे अड़ौसी नै पड़ौसी तैं कोए मतलब ना होता। पर गाम में अड़ौसी भी चाहिए और पड़ौसी भी चाहिए। रळ मिलकै रहा करैं। एक दूसरे का सहयोग करैं। सुख-दुख साझा करैं। जिबै बढ़िया टैम पास होया करै।

-छबीले, पर यू जिक्रा आज कितोड़ तैं आग्या? के कहणा चाहवै सै?

-रसीले मैं ये बात न्यूं कहूं सूं अक जिस गाम की गली तंग सैं और उनमें ढंग तै घरां के निकासी के पानी की ठीक व्यवस्था नहीं सै, उड़ै अड़ोसी-पड़ौसी का जूत देर सबेर बाजे जा सै। उस रामेहर की बहू नै देखले, दूसरे तीसरे दिन म्हारे बारणै निकासी का पानी फैंक दे सै। के कहा जा? हाम तो परेशान हो लिए। दो बार सरपंच तैं कह ली अक म्हारी गाल ठीक तरियां बनवा दे ताकि घरां का पानी ठीक लिकड़ज्या। पर कोन्या गौर करता।

-भाई परेशानी आली बात तो सै। रामेहर नै यो बात समझणी चाहिए। हल्के में नहीं लेणी चाहिए। देख छबीले इस समस्या का समाधान तो तमनै मिल बैठकै करणा पड़ैगा। रौळा करे तैं कोए काम सुधरा नहीं करता, बिगड़या करै। महामारी का टैम चालर्‌या सै। गंदगी फैलैगी तो कोए बीमार होज्यागा। अड़ौसी की बीमारी पड़ौसी कै लागज्यागी। इसलिए प्रेम तैं बैठकै निकासी के पानी का समाधान करो। देख छबीले मेरा घर गाम तै बाहरवाई सै। निकासी के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं बणै था। मनैं सारा पाणी खड्डे में कट्ठा कर लिया, दूसरे तीसरे दिन क्यारी में छोड़ दे सैं जड़ै सब्जी बो राखी सैं।

-तूं ठीक सै छबीले, पर म्हारा मकान तो गाम के बीच में सै। उड़ै तो सब्जी कोन्या बोई जा ।

-रसीले, मरोड़ कै तो करोड़ लाग्या करैं। गली में उरेन-परेन गंदगी फैलैगी तो बीमारी फैलैगी। बीमार होज्याओगे तो डाक्टर कै जाणा पड़ैगा। खर्चा होगा, बीरानमाटी होगी। इसतै आच्छा सारे मिल-बैठकै समस्या का समाधान करैंगे। सरपंच धोरै बात नहीं बणी तो बीडीपीओ धोरै चालैंगे। गाल भी बणवावैंगे और निकासी के पाणी का बंदोबस्त भी करावैंगे।

-हां छबीले सरकार भी कहै सै अक पीस्से की कमी कोन्या, काम करवाणे आले होणे चाहिंए।

-भाई घरां बैठे कोए न्यू कोन्या पूछण आवै अक थाम राजी सो अक नाराज सो। हाथ पां हिलाये तैं और घर तैं बाहर जाए तैं काम होया करैं। न्यू भी कहा करैं काम छोड्‌े काम हो सैं। पर दुर्भाग्य तो यू सै रसीले लोग न्यू चाहवैं सैं अक बिना कुछ हाथ पां हिलाए सरकार ए सारे काम कर दे। और वे सारा दिन ताश पीटे जां। चाल चालैंगे, काल कर्‌या सो आज कर। गाम में साफ सफाई राखणी बोहत जरुरी सै। रोज तड़कै गली में खुद बुहारी दिया करूं। के पार्क करैंगे। मैं तो सारे गाम आल्यां नै हाथ जोड़कै कहूं सूं रसीले, अक वे गलियां में डांगर बांधण की कोशिश ना करैं।

-मनोज प्रभाकर

मस्त हरियाणा

हरियाणा के गांव-गांव में ,
मिल जायेंगे बंगले-कोठी ।
यहां बड़े चाव से खाते हैं ,
घी-शक्क र के साथ रोटी ।।

तेज बहाव से बहती यमुना
करनाल-पानीपत के पास ।
सचमुच सोने जैसी मिट्टी में ,
उपजे गेहूं-चावल खास ।
अंगूर-अमरूद के बागों से ,
लोग करते कमाई मोटी ।।
यहां बड़े चाव से खाते हैं ,
घी-शक्क र के साथ रोटी ।।

कार-ट्रैक्टर के कारखाने ,
गुरुग्राम-फरीदाबाद में ।
आलू-गोभी जैसी सब्जियां ,
उपजाये देशी खाद में ।
घर-घर में दही-मक्खन की
देखो मटकी बड़ी-छोटी ।।
यहां बड़े चाव से खाते हैं ,
घी-शक्क र के साथ रोटी ।।

शिक्षा-संस्कार की बात हो ,
चाहे खेल-कूद का मैदान ।
देश की सेना में शामिल ,
हजारों-लाखों नौजवान ।।
मस्त हरियाणा के आदमी ,
कहे सामने खरी-खोटी ।।
यहां बड़े चाव से खाते हैं ,
घी-शक्क र के साथ रोटी ।।

हरियाणा के गांव-गांव में ,
मिल जायेंगे बंगले-कोठी ।
यहां बड़े चाव से खाते हैं ,
घी-शक्क र के साथ रोटी ।।

- बलजीत सिंह
ग्राम राजपुरा (सिसाय)

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com